

01-2-2018

428

C&T(Hu)

12/2/18

उत्तराखण्ड लोक वि. वि.

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
विभागाध्यक्ष
संख्या: /XXXI(15)G/17-51(सा0)/2018
01 FEB 2018
उत्तराखण्ड लोक वि. वि. देहरादून

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग

देहरादून: दिनांक 29 जनवरी, 2018

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन खोली गयी पत्रावलियों के निर्दान (weeding) किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों व उनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में सरकारी अभिलेखों को निर्धारित अवधि तक रखे जाने व उसके बाद विनिष्टीकरण की कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था समुचित रूप से लागू नहीं हो पा रही है। कार्यालयों में अभिलेखों के रख रखाव व विनिष्टीकरण की व्यवस्था न किये जाने से पुराने व अनुपयोगी अभिलेखों के अव्यवस्थित पड़े रहने से कार्यालयों में अनावश्यक स्थान घिरा रहता है जिससे कर्मचारियों को कार्य करने में कठिनाई होती है। कई बार फाइलों में पुराने एवं महत्वहीन पत्रजातों के रक्षित होने के कारण नए पत्रों को तलाशने एवं तत्पश्चात कार्यालयी प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने में महत्वपूर्ण समय नष्ट होने के साथ साथ कार्य करने में अनावश्यक विलम्ब होता है।

2. शासनादेश संख्या-244/XXXI(13)G/2005 दिनांक 23 अप्रैल, 2005 के द्वारा सभी अभिलेखों की अवधि के रख रखाव के निर्देशों का निर्धारण विस्तार से किया गया है। उक्त शासनादेश में विस्तार करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत खोली गयी, पत्रावलियों, जिनकी उपयोगिता नहीं रह गयी है, ऐसे अभिलेखों के निर्दान (weeding) हेतु निम्नवत दिशा-निर्देश एतद्वारा प्रख्यापित किये जाते हैं:-

(क) ऐसी पत्रावली, जिसमें चाही गयी सूचनाएं लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को प्रदान की जा चुकी हो और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 में दी गयी समयावधि के अन्दर प्रथम एवं द्वितीय अपील योजित नहीं हुयी हो, को सूचना प्रदान करने की तिथि के एक वर्ष बाद निर्दान (weeding) किया जाय।

(ख) ऐसी पत्रावली जिसमें लोक सूचना अधिकारी द्वारा किये गये विनिश्चय या दी गयी सूचनाओं से व्यथित होकर आवेदक ने प्रथम या द्वितीय अपील की हुयी हो और प्रकरण की प्रथम विभागीय अपील या द्वितीय अपील की सुनवायी लंबित हो या दी गयी

A G HOJ
01/02/18
CAO

257
SSO I
S/O 2018

